कलम का सौदा

हिन्दी साप्ताहिक

राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से विज्ञापनों के लिए मान्यता प्राप्त

www.kksnews.com

वर्ष 17 अंक 02 हरिद्वार 09 अगस्त 2022 डाक पंजीयन संख्या: UA/DO/DDN/275/2015-2017 R.N.I. No. UTTHIN/2006/17725 मूल्य 1रुपया पृष्ठ 4

उत्तराखण्ड में बीएसएनएल के 1206 मोबाइल टावर की स्वीकृति

नई दिल्ली/देहरादून (सू.वि.)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री, रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना तकनीक अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार भेंट की। उत्तराखण्ड में मोबाइल नेटवर्क को मजबूत करने के मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखण्ड में बीएसएनएल के 1206 मोबाइल टावर की स्वीकृति दी।

प्रत्येक मोबाईल टावर की लागत 1 करोड़ रुपये आएगी। मुख्यमंत्री ने टनकपुर-देहरादून के मध्य एक जनशताब्दी रेल सेवा शुरू किये जाने का भी अनुरोध किया।

रूड़की-देवबन्द रेल परियोजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से अब तक प्रदत्त अंशदान की धनराशि 296.67 करोड़ को अंतिम करते हुए 50 प्रतिशत अंशदान के सापेक्ष शेष देय धनराशि 99.01 करोड़ का भुगतान करने से राज्य सरकार को मुक्त करने का भी आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में कुमाऊँ और गढ़वाल को जोड़ने के लिए देहरादून-काठगोदाम के मध्य चलने वाली एक मात्र रेल सेवा है। नेपाल बोर्डर होने के कारण वहाँ के लिए लोगों का आवागमन टनकपुर से ही होता है। इसलिए कुमाऊं-गढवाल कनेक्टिवीटी को और मजबूत करने के लिए टनकपुर-देहरादून मार्ग पर एक जनशताब्दी रेल को संचालित किया जाना जनहित में अत्यंत आवश्यक है।

केंद्रीय मंत्री, रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना तकनीक अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार भेंट करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

मुख्यमंत्री ने टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को नेरोगेज के स्थान पर ब्रोडगेज बनाये जाने, हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन को डबल लेन बनाने, हर्रावाला रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण, ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन तथा किच्छा-खटीमा रेल लाइन के निर्माण हेतु भी अनुरोध किया। जिनके संबंध में रेल मंत्री द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

मुख्यमंत्री द्वारा टनकपुर से दिल्ली के मध्य चलने वाली पूर्णागिरी जन शताब्दी की यात्रा अवधि को कम करते हुए 5-6 घंटों में यात्रा पूर्ण कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करने का भी अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रूड़की-देवबन्द रेल परियोजना के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा विगत में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत वहन करने हेतु प्रदत्त सहमति के क्रम में कुल परियोजना लागत रूपये 791.39 करोड़ के सापेक्ष उत्तराखण्ड राज्य द्वारा अब तक रूपये 296.67 करोड़ का अंशदान रेलवे को दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रेल मंत्री से उत्तराखण्ड जैसे छोटे एवं पर्वतीय राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से अब तक प्रदत्त अंशदान की धनराशि को अंतिम करते हुए 50 प्रतिशत अंशदान के सापेक्ष शेष देय धनराशि 99.01 करोड़ का भुगतान करने से राज्य सरकार को मुक्त करने का अनुरोध किया।

दर्ज कराएं शिकायत, लापरवाहों का होगा 'इलाज'

हरिद्वार (संवाददाता)। जिला अस्पताल प्रशासन ने व्यवस्थाओं में सुधार और मरीजों को बेहतर सुविधा देने के लिए एक नई पहल शुरू की है। अब यदि किसी भी मरीज को अस्पताल में सही उपचार नहीं मिले या किसी तीमारदार को कोई शिकायत हो तो इसके लिए वह अपनी समस्या शिकायत पंजिका में दर्ज कर सकता है। यह व्यवस्था आज मंगलवार से शुरू हो जाएगी। शिकायतों की सुनवाई और निस्तारण सीएमएस करेंगे। यदि इस मामले में अस्पताल के किसी चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ की तरफ से लापरवाही सामने आई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।सौ बेड के जिला अस्पताल पर शहर के अलावा देहात के लोगों के स्वास्थ्य की भी जिम्मेदारी है।

हर रोज यहां बड़ी संख्या में मरीज उपचार कराने के लिए पहुंचते हैं। मरीज और तीमारदारों की शिकायत रहती है कि उन्हें अस्पताल में सही उपचार नहीं मिल पता। यह बात कई बार अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाती।

कई बार गरीब लोगों की सुनवाई भी नहीं होती। इस समस्या को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने शिकायत पंजिका में शिकायत दर्ज करने और उसके निस्तारण की पहल की है।जिला अस्पताल के वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डॉ. चंदन कुमार मिश्रा ने बताया कि उपचार कराने के लिए पहुंचने वाले मरीज और तीमारदार कई तरह की शिकायतें लेकर कार्यालय में आते हैं। शिकायतें लिखित में नहीं होती थी। इसलिए कार्रवाई नहीं हो पाती है। अस्पताल परिसर में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और लापरवाह कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मंगलवार से तीन कार्यालयों में शिकायत पंजिका उपलब्ध होगी। मरीज और तीमारदार अपना नाम पता और मोबाइल नंबर अंकित कर शिकायत पंजिका में दर्ज करा सकेंगे।

शिकायत पंजिका में चिकित्सक, दवा, उपचार और कर्मचारियों के व्यवहार के अलावा अस्पताल से जुड़ी अन्य शिकायतों को भी दर्ज कर सकेंगे। पंजिकाओं में दर्ज होने वाली शिकायतों का सीएमएस स्वयं संज्ञान लेंगे। गंभीर शिकायतों पर कार्रवाई भी की जाएगी। शिकायत रजिस्टर इंडोर कार्यालय, सीएमएस कार्यालय और इमरजेंसी वार्ड में रखे जाएंगे। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा और मरीजों व तीमारदारों को भी सुविधा होगी।

22 अगस्त से काली पट्टी बांधेंगे सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी

देहरादून (संवाददाता)। सर्वे ऑफ इंडिया की ग्रुप बी(राजपत्रित अधिकारी संघ)की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की दो दिनी बैठक हाथीबड़कला एस्टेट में सम्पन्न हुई।

बैठक में पदोन्नति, स्थानांतरण, वेतन अपग्रेडेशन, सर्विस नियमावली में संशोधन की मांग पूर न होने पर 22 अगस्त से काली पट्टी बांधकर विरोध जताने का आह्वान किया गया। भारतीय मजदूर संघ से सम्बंध ग्रुप बी अधिकरी संघ के अध्यक्ष वेद प्रकाश श्रीवास्तव, महासचिव उमेश मिश्रा ने बताया कि बैठक में भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री(उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली व नेपाल) अनुपम, प्रदेश मंत्री सुमित सिंघल, दून जिलाध्यक्ष अजय कांत शर्मा ने आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया। मौके पर उपाध्यक्ष अरुण सैनी, कोषाध्यक्ष राकेश कुमार, राजीव गुप्ता, संजय सक्सेना, एम वासुदेव, समीर सांत्र, नारायण धड़ाई, भुवनेश्वर, केवी रमेश, मंजीत सिंह, प्रवेश कुमार, सुनील कुमार ने हिस्सा लिया।

न्यूज अपडेट्स

फर्जी फेसबुक आइडी बनाकर धोखाधड़ी करने वाला आरोपित गिरफ्तार

देहरादून (संवाददाता)। आमजन की फर्जी फेसबुक आइडी बनाकर उनके दोस्त व रिश्तेदारों से रुपये मांगने वाले आरोपित को साइबर थाना पुलिस ने हरियाणा के मेवात से गिरफ्तार किया है। आरोपित के पास से मोबाइल फोन बरामद किया गया है, जिससे वह धोखाधड़ी करता था। सीओ साइबर क्राइम अंकुश मिश्रा ने बताया कि तीन जून 2021 को देहरादून निवासी नीलाभ किशोर ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि उनकी फर्जी फेसबुक आइडी बनाकर कोई उनके दोस्तों और रिश्तेदारों से रुपये मांग रहा है। मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपित को पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर देवेंद्र नबियाल के नेतृत्व में टीम गठित की गई। जांच के दौरान सामने आया कि उक्त फर्जी फेसबुक आइडी हरियाणा के मेवात क्षेत्र से संचालित हो रही है। इस पर पुलिस टीम मेवात रवाना हुई। जहां पुलिस ने शुक्रवार को आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित की पहचान अशफाक निवासी ग्राम सिंगार बिचौल, जिला नूह, मेवात, हरियाणा के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम चलाने वाले व्यक्तियों की आइडी का विश्लेषण कर नाम, प्रोफाइल फोटो व अन्य जानकारी हासिल करता है। इसके बाद उसी व्यक्ति के नाम की फर्जी आइडी बनाकर उनके दोस्तों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर मदद के नाम पर रुपये मांगता है।

हुड़दंग मचाने वाले आठ युवक व तीन युवतियां गिरफ्तार

देहरादून (संवाददाता)। देर रात सड़कों पर घूमकर हुड़दंग मचाने वाले तीन युवतियों सहित आठ आरोपितों को पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनका पुलिस एक्ट में चालान करते हुए उन्हें हिदायत देकर छोड़ दिया। इंस्पेक्टर रविंदर यादव ने बताया कि देर रात पुलिस टीम गश्त कर रही थी। इसी दौरान बाजार चौकी इंचार्ज सनोज कुमार को सूचना मिली कि निरंजनपुर सब्जी मंडी क्षेत्र में कुछ युवक युवतियां हुड़दंग मचा रहे हैं।

पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और उन्हें हिरासत में लिया।

सम्पादकीय

सख्त सजा देने में

डिजिटल सेंधमारी में एक किस्म है फिशिंग की, यानी बैंकों के क्रेडिट कार्ड आदि की जानकारी चुरा कर रकम उड़ा लेना। दूसरी किस्म है– रैंसमवेयर यानी फिरौती की। इसमें लोगों, कंपनियों के कंप्यूटर नेववर्क पर साइबर हमला कर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया जाता है और इसके बदले में भारी–भरकम फिरौती वसूली जाती है। विश्लेषण में पता चला है कि पिछले साल की तुलना में फिशिंग में ग्यारह फीसद और रैंसमवेयर में छह फीसद की बढ़ोत्तरी हुई।साइबर अपराध की तीसरी किस्म सोशल मीडिया पर मौजूद लोगों को किसी न किसी तरीके से अपमानित करने वाले अपराध की है, जो सुल्ली–बुल्ली बाई जैसे ऐप की मार्फत किए जा रहे हैं। पिछले डेढ़–दो साल में ही लोगों के बैंक खातों, निजता यानी पहचान से जुड़े डाटा पर हाथ साफ करने जैसे मामलों में साढ़े छह सौ फीसद का इजाफा हुआ है। भारत में ऐसी घटनाओं की सालाना संख्या छह–सात लाख तक पहुंच गई है।यहां बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर ऐसे साइबर अपराधों की रोकथाम कैसे हो। हालांकि कानूनी उपाय इसका एक रास्ता है। लेकिन बात सिर्फ कानून बनाने मात्र से नहीं बन रही है। चूंकि साइबर अपराधी अब अंतरदेशीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गिरोह बना कर काम कर रहे हैं, इसलिए खातों से उड़ाई गई रकम रातों–रात एक देश से बाहर दूसरे ठिकानों पर चली जाती है।इसी तरह बुल्ली बाई जैसे ऐप जिस गिटहब नामक मंच पर बन रहे हैं, वे विदेशों से संचालित हो रहे हैं। ऐसे में देश के कानून बेमानी हो जाते हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल उन लोगों के लिए है जिन्हें बैंकिंग, खरीदारी के वर्चुअल विकल्प मजबूरी में (जैसे कि कोरोना काल में) अपनाने पड़े हैं और जिन्हें इन साइबर उपायों की समझ व जानकारी बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोग एटीएम से पैसे निकालने के लिए अक्सर अनजान लोगों की मदद लेते हैं और उन्हें अपने एटीएम का पिन नंबर तक बता डालते हैं।जाहिर है, डिजिटल प्रबंधों को जरूरी बनाने के साथ सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह कानून बनाने के साथ कड़ी सजाओं के प्रावधान भी करे और साइबर थानों में दर्ज हर शिकायत पर कार्रवाई सुनिश्चित करे। अभी तो आलम यह है कि साइबर पुलिस हील–हुज्जत के बाद शिकायत दर्ज करने के अलावा कोई और काम नहीं करती। अक्सर पीड़ितों को खुद ही बैंकों और पुलिस थानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ध्यान रहे कि हमारे देश में खाली बैठे–ठाले शातिर लोगों और बेरोजगारों की एक बड़ी फौज अमेरिका–ब्रिटेन तक के नागरिकों को फर्जी काल सेंटर आदि के जरिए लूटने पर आमादा है। ऐसे में यदि साइबर अपराधियों की धरपकड़ कर उन्हें बेहद सख्त सजा देने में तेजी नहीं लाई गई, तो यह मर्ज एक लाइलाज महामारी की तरह ही बढ़ता जाएगा।

खर्च रुपैया की तर्ज पर

सनत कुमार जैन

केंद्र एवं राज्य सरकारें जन-कल्याणलकारी योजनाओं, विकास कार्यों, मंत्रियों, विधायकों, सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों, सरकारी कार्यालयों के खर्च के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज ले रही हैं। राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए राज्यों को रिजर्व बैंक से जीडीपी, के मानदंड से कर्ज लेने की सुविधा है। पिछले एक दशक में केंद्र एवं राज्य सरकारों ने बड़े पैमाने पर कर्ज लेना शुरु कर दिया है। आमदनी अठ्ठन्नी और खर्च रुपैया की तर्ज पर बजट को बढ़ा-चढ़ाकर बनाने का नया पैतरा शुरु हो गया।

वैश्विक वित्तीय संस्थाओं द्वारा विकास कार्यों एवं जन-हितकारी योजनाओं के लिए वर्ष 2004 के बाद केन्द्र एवं राज्यो को कर्ज देना शुरु किया। केंद्र एवं राज्य सरकारों ने वैश्विक वित्तीय संस्थाओं से विकास योजनाओं के नाम पर बड़ा विदेशी कर्ज लिया।

इस होड़ में सरकारों के साथ-साथ स्थानीय निकायों ने भी कर्ज लेना शुरु कर दिया है। प्रत्येक नगर निगम और नगर पालिकायें कर्ज के बोझ से दबी हुई है। अब कर्ज की यह गंगा गांव-गांव तक पहुंच रही है। केंद्र की कई योजनायें ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंच रही हैं। ग्राम सरकार भी वैश्विक कर्ज की शिकार हो गई है।

केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों तथा पंचायतें भी कर्ज का शिकार है। पिछले एक दशक में केंद्र एवं राज्य सरकारों ने टेक्स बढ़ाये हैं। आम आदमी पर टेक्स के दायरे को राज्य सरकारों, नगरीय संस्थाओं ने पिछले एक दशक में बढ़ाया। अब ग्राम पंचायतों में भी पानी, सम्पत्तिकर इत्यादि का प्रावधान कर दिया गया है। सेवाओं के शुल्क अलग से वसूल किये जा रहे है। नगरीय संस्थाओं ने टेक्स एवं शुल्क को कई गुना बढ़ा दिया है। नागरिकों से टैक्स एवं शुल्क के रुप में वसूली कई गुना हो गई। इसके बाद भी जनता के टेक्स और शुल्क से वसूल की गई राशि से ब्याज और सरकारी खर्च पूरा नहीं हो पा रहा है। जिसके कारण नए-नए टेक्स और शुल्क हर साल बढ़ रहे हैं। इसके बाद भी सरकारों का कर्ज सुरसा की भांति बढ़ता ही जा रहा है।

निर्वाचित प्रतिनिधि पांच वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। अधिकारियों की तैनाती भी दो से तीन वर्ष की होती है। कर्ज टेक्स एवं शुल्क के रुप में प्राप्त राजस्व को दोनों हाथों से खर्च करने एवं उसका हिस्सा प्राप्त कर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। अब स्थिति बदल रही है। राजनीति धंधा बन गई है। सांसदों, विधायको, मंत्रियों, राजनेताओं, अधिकारियों के परिवार में सरकारी टेकों एवं सप्लाई से कमाई हो रही है। एक बार विधायक, सांसद, मंत्री बन जाने पर 7 पीड़ियों के लिए कमाई करने का नया धंधा राजनीति बन गया है। कर्ज का बोझ एवं टेक्स जिस स्तर तक लिया जा सकता था। वह केंद्र, राज्य सरकारें एवं स्थानीय निकाय ले चुके हैं। आम जनता पर जितने टेक्स लादे जा सकते थे। वह लाद दिये गए। कोरोना संक्रमण, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी एवं मंहगाई ने आम आदमी की आर्थिक स्थिति को दय से दयनीय स्थिति पर पहुंचा दिया है। आम आदमी के उपर भी भारी कर्ज है। कर्ज की किस्त चुका पाना भी आम आदमी के बस में नहीं है। बैंकों एवं एनएफसी कम्पनियों का एनपीए लगातार बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में कर्ज लेकर घी पीने वाली अर्थव्यवस्था में अब ठहराव आ गया है। जिसका असर केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, रिजर्व बैंक, बैकों, वित्तीय संस्थाओं के साथ-साथ राजकोषीय घाटे पर पड़ रहा है।

रिजर्व बैंक की 2022 की रिपोर्ट के तथा स्टेट फाइनेंस स्टडी रिपोर्ट के अनुसार सभी राज्यों पर 70 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। राज्य सरकारों का राजकोषीय घाटा 8.19 लाख करोड़ हो गया है। जो सकल जीडीपी का 31 फीसदी पर पहुंच गया है। पंजाब, राजस्थान, प.बंगाल, गुजरात तथा हरियाणा राज्यों पर सबसे ज्यादा कर्ज है। लगभग सभी राज्यों के आय की तुलना में खर्च ज्यादा है। केन्द्र एवं राज्यों के राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए सरकारों को अपने खर्च में कटौती करना पड़ेगी। केंद्र की तरह राज्यों द्वारा भी सार्वजनिक उपक्रमों की सम्पत्ति बेची जा रही है। उसके बाद भी वित्तीय नियंत्रण नहीं हो पा रहा है।

केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और राज्य सरकारों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। कर्ज के उच्चतम स्तर पर पहुंचकर सरकारों के बढ़ते खर्च पर रोक लगने के सिवाय अब कोई रास्ता नहीं रहा। दो दशक पहिले भी देश इस स्थिति से गुजर चुका है। प्रशासनिक खर्च में कमी, वेतन-भत्तों में कमी तथा उपलब्ध धन के आधार पर ही केंद्र, राज्य सरकारों और स्थानीय संस्थाओं को विकास योजनायें और खर्च को नियंत्रित करना होगा। वर्तमान स्थिति में अर्थ-व्यवस्था का पहिया उल्टा घूमना शुरु हो गया है। भारत की अर्थ-व्यवस्था 25 वर्ष पीछे की ओर जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के समय राज्यों के बढ़ते कर्ज में लगाम लगाने तथा वित्तीय स्थिति को सुधारने के जो प्रयास किये गये थे। वही प्रयास एक बार फिर शुरु करना होंगे। कर्ज की अर्थव्यवस्था और ब्याज से मुक्ति पानी होगी। उसके बाद भी अर्थ-व्यवस्था को नियंत्रित कर पाने में कई वर्ष लगेंगे।

यथा नाम तथा गुण, धीर बनो अधीर भाई

अनिल बिहारी श्रीवास्तव

अधीररंजन चौधरी एक जाना-पहचाना नाम है। इसकी वजह व्यवहार, टिप्पणियां और गांधी परिवार के प्रति वफादारी का बारम्बार प्रदर्शन को मान सकते हैं।

समझने के लिए एक ताजा उदाहरण काफी है। सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही पूछताछ पर स्वयंभू वफादार कांग्रेसियों का भड़कना स्वाभाविक है लेकिन आश्चर्य तो उनमें से कुछेक के तमतमाते अंदाज को देख कर हुआ। सांसद अधीररंजन चौधरी ऐसे कांग्रेसियों की पहली जमात में हैं। सोनिया गांधी से पूछताछ पर उनकी नाराजगी और बौखलाहट का अलग ही अंदाज देखने में आया। वह मीडियाई कैमरों के सामने फट से पड़े-श्सरकार ने ईडी को इडियट बना दिया।

कभी कोई विश्वास नहीं करेगा कि जिस पार्टी ने 54 सालों तक देश में राज किया वह 90 करोड़ का घोटाला करेगी।श् जहां तक जुबान बेकाबू होने की बात है, तो चौधरी के संदर्भ में इसे पहला या एकमात्र नमूना नहीं कह सकते। वह गुजरात एसआईटी के लिए अपमानजनक शब्द कह चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने पर एक सांसद उनके विरूद्ध विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे चुका है। इसी 15 जुलाई को उन्होंने कहा था, श्राहुल गांधी के साथ अमानवीय व्यवहार ईडी कर रही है।श् ईडी पर अधीररंजन चौधरी की ताजा टिप्पणी का उत्तर डा.सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस अंदाज में दिया वह बोलती बंद कर देने वाला रहा। स्वामी ने ट्वीट किया-श्अधीर ने ईडी को इडियट्स का नेतृत्व करने वाला बताया है। ऐसा लगता है कि वह भूल गए हैं कि ईडी डायरेक्टर का चयन तीन सदस्यीय समिति द्वारा किया जाता है जिसमें सीजेआई, पीएम और लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। सुपर इडियट हैं अधीररंजन चौधरी।श् स्वामी के ट्वीट पर उनकी प्रतिक्रिया नहीं मिली। सोशल मीडिया पर लोग चौधरी के खूब मजे लिए। किसी ने कटाक्ष किया-श्यथा नाम तथा गुण, धीर बनो अधीर भाई।श्

इस बार मीडियाई कैमरों पर छाये रहने के मामले में दूसरा नाम अशोक गेहलोत का लिया जा रहा है। अधीर रंजन की तरह अशोक गेहलोत के बयान पर भी लोग हंस रहे हैं। गेहलोत का मानना है कि सोनियाजी के आभामंडल और उनके व्यक्तित्व को देखते हुए उन्हें ईडी दफ्तर में बुलाया जाना ठीक नहीं था। बकौल गेहलोत, श्ईडी सोनिया जी के घर जाकर पूछताछ कर सकते थे।श् गेहलोत यहीं नहीं रुके। वह मानते हैं कि राजनीतिक विद्वेष के चलते पूछताछ के लिए यह सब किया जा रहा है। ईडी और सीबीआई का व्यवहार काफी निचले स्तर का है। गेहलोत और चौधरी के विचार हास्यास्पद नहीं लगते? इस समय कांग्रेस में वफादारी दिखाने की होड़ में और भी नाम हैं। कोई कथित सत्याग्रह में शामिल होकर वफादारी दिखाता रहा और किसी के चेहरे पर महज इस बात के लिए मायूसी देखी गई क्योंकि वह गिरफ्तारी देने से चूक गया। सियासी डायलॉग की झड़ी लगी थी। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के दौरान ईडी के समक्ष सोनिया गांधी जिस समय सवाल-जवाब में उलझीं थीं, वहां बाहर सत्याग्रह के नाम पर बचे-खुचे कांग्रेसी वफादारी साबित करने में लगे थे। विशुद्ध राजनीतिक प्रपंच देश ने देखा। राहुल गांधी से हुई 50 घण्टे की पूछताछ के समय भी यही तमाशा किया गया था। इससे हुआ क्या? ना तो ईडी पर कोई दबाव दिखा और ना ही सरकार ने उनकी ओर देखने की जरूरत महसूस की। कांग्रेसियों ने खुद ही अपना मजाक बनवा लिया। आश्चर्य होता है। ऐसे तमाशे रोकने की जरूरत हाईकमान ने महसूस नहीं की। सुचिता को लेकर बातें खूब की जाती हैं फिर उसका प्रमाण देने में झिझक क्यों होनी चाहिए? पवित्रता और आदर्शों को लेकर भी जमकर कहा जाता रहा है। सवाल यह है सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर अंगुली उठी है तो उनसे पूछताछ क्यों नहीं हो? ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठा कर या केंद्र सरकार के इशारे पर विरोधियों को परेशान करने का आरोप लगा कर ऐसी संस्थाओं की छवि बिगाड़ने जैसी हरकतों को आम आदमी समझने लगा है। प्रमाण सामने है। सोनिया और राहुल से पूछताछ के विरोध में हुआ तमाशा बेअसर साबित हुआ है। एक राजनीतिक विश्लेषक के अनुसार यूपीए सरकार के कार्यकाल में ईडी को जो कानूनी ताकत दी गई थी उसी का उपयोग किया जा रहा है। फिर कांग्रेस इतना परेशान क्यों हो रही है। ईडी की स्थापना 1956 में हुई थी। समय के साथ हुए कानून में संशोधनों और दी गई शक्तियों के उपयोग से बड़े चौंका देने वाले परिणाम सामने आए हैं। इसी वर्ष फरवरी माह में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि प्रिवेंशन आफमनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 98 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सम्पत्ति अटैच की जा चुकी है लेकिन सजा सुनाये जाने की दर कम है। बताया गया कि बैंकों के साथ 22585 करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी करने वाले विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी यह 19111 करोड़ की सम्पत्ति अटैच की गई। इसमें से 15114 करोड़ की सम्पत्ति ठगी का शिकार बैंकों को लौटाई गई है। राजनीतिक संबंधोंध्सम्पर्कों का फायदा उठा कर ही बैंकों के साथ अब तक की यह सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी की गई थी। ईडी की शक्तियां बढ़ाने और उसको खुली छूट दिये जाने के अच्छे नतीजे मिलने लगे हैं। गलत तरीकों से धन कमाने वाले आर्थिक अपराधियों और सियासत को चारागाह समझ बैठे सियासत दां की बेचैनी साफदिखाई देती है।

उत्तराखंड आयुर्वेद विवि में विजिलेंस की खुली जांच शुरू

◆भर्तियों में धांधली का मामला

◆कमेटी के पदाधिकारियों से की गई पूछताछ

उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

देहरादून (संवाददाता)। साल 2015 में उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून में हुई नियुक्तियों की घपलेबाजी मामले में विजिलेंस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। विजिलेंस की टीम ने विश्वविद्यालय में कार्रवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं। इंस्पेक्टर किरण असवाल के नेतृत्व में बनाई गई विजिलेंस की टीम ने विश्वविद्यालय में भर्ती करवाने वाली कमेटी के पदाधिकारियों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए हैं।

जानकारी के मुताबिक 2015 में उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में योग अनुदेशकों के पद पर जारी रोस्टर को बदलने और माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पदों पर भर्ती में घपलेबाजी का आरोप है। बायोमेडिकल संकाय और संस्कृत असिस्टेंट प्रोफेसर सहित पंचकर्म सहायक के पदों पर विज्ञप्ति प्रकाशित कर उसे रद्द करने का मामला भी है।

विश्वविद्यालय में रिक्त पद ना होते हुए भी संस्कृत शिक्षकों को प्रमोशन और एसीपी का भुगतान करने के अलावा शासन से बिना अनुमति के ही अलग-अलग पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकालने का आरोप है। वहीं, विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विश्वविद्यालय की ओर से गठित समितियों द्वारा विस्तृत जानकारी शासन को न देने के साथ ही पीआरडी के माध्यम से 60 अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करने का भी आरोप है।

इसके अलावा विश्वविद्यालय में अलग-अलग तरह के सामान खरीदने में वित्तीय गड़बड़ी करने के आरोप भी संस्थान की प्रबंधक टीम पर लगे हैं।

बता दें, इस मामले में मई 2022 को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विजिलेंस को आयुर्वेद विश्वविद्यालय की खुली जांच करने के आदेश दिए थे। ऐसे में विजिलेंस की ओर से नोटिस देकर विश्वविद्यालय प्रशासन को पूछताछ में सहयोग करने और भर्ती दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। लेकिन बार-बार रिमाइंडर के बावजूद विश्वविद्यालय की तरफसे किसी अधिकारी व कर्मचारी के ना पहुंचने की सूरत में विजिलेंस टीम ने विश्वविद्यालय पहुंचकर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। विजिलेंस की खुली जांच शुरू होते ही विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया। विजिलेंस ने इस दौरान प्रशासनिक भवन में सभी बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दी। सभी कर्मचारियों को संस्थान से बाहर निकलने पर भी रोक लगा दी। विजिलेंस की टीम ने पहले दिन घंटों तक जांच-पड़ताल करते हुए भर्ती रिकॉर्ड खंगाले। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान लेकर अनिमितताओं से जुड़े दस्तावेज भी अपने कब्जे में लिए हैं।

शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत प्रवेश के लिए प्रक्रिया 5 अगस्त से हुई शुरू

देहरादून (संवाददाता)। शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए 21 अप्रैल को बच्चों के प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी जो कि 20 जुलाई को पूरी हो गई थी। शिक्षा विभाग का अनुमान है कि अभी भी शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत आने वाले काफी संख्या में छात्र प्रवेश से वंचित रह गए हैं। इसी के मद्देनजर प्रवेश की प्रक्रिया को 5 अगस्त से दोबारा से शुरू करा दिया गया है शिक्षा का अधिकार के तहत मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए सरकार ने छात्र-छात्राओं को एक अवसर और दिया है। सरकार ने यह अवसर स्कूलों में निर्धारित कोटे से कम प्रवेश होने के कारण प्रदान किया है। शुक्रवार को दोबारा से शुरू हो रही प्रवेश की यह प्रक्रिया 25 अगस्त तक चलेगी।

शिक्षा का अधिकार के तहत सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा आठ तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इसी अधिकार के तहत शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए 21 अप्रैल को बच्चों के प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी जो कि 20 जुलाई को पूरी हो गई थी।

प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद शिक्षा विभाग को प्राप्त हुए आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के कुल 13 जनपदों में 24 हजार 43 छात्र-छात्राओं ने शिक्षा का अधिकार के तहत प्रवेश के लिए प्रक्रिया को पूरा किया है, जिनमें कुल 12472 बालक व 11571 बालिका शामिल हैं।

शिक्षा विभाग का अनुमान है कि अभी भी शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत आने वाले काफी संख्या में छात्र-छात्राएं प्रवेश से वंचित रह गए हैं। इसी के मद्देनजर आरटीई के तहत होने वाले प्रवेश की प्रक्रिया को 5 अगस्त से दोबारा से शुरू करा दिया गया है, जिससे प्रदेश के कई हजार वंचित वर्ग के छात्र-छात्राओं को मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलने की उम्मीद है।

मुख्य शिक्षा अधिकारी मुकुल कुमार सती के मुताबिक शिक्षा का अधिकार के तहत प्रवेश से वंचित बच्चों के एडमिशन की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। प्रवेश से वंचित छात्र-छात्राओं को एक अवसर और दिया गया है।

देहरादून जनपद में शिक्षा का अधिकार के तहत 2022-23 सत्र में 8688 छात्र-छात्राओं को पंजीकरण हुआ है, जिसमें 4457 बालक एवं 4231 बालिका हैं।

24 घंटे से ज्यादा समय हो गया जांच चलते हुए

देहरादून(संवाददाता)। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में शनिवार को भी विजिलेंस की जांच पड़ताल जारी रही। नोटिस के बावजूद संस्थान अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा जांच में सहयोग न करने के चलते विजिलेंस ने कड़ा रुख अख्तियार कर दिया है।

यही कारण है कि अब विजिलेंस की टीम शनिवार को संस्थान पहुंचकर जांच की कार्रवाई में तेजी लाने की योजना बना चुकी है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में जल्द ही कई अधिकारियों व कर्मचारियों पर कानूनी शिकंजा कसने के साथ ही विभागीय गाज भी गिर सकती है। अभी तक की विजिलेंस जांच में भर्ती धांधलेबाजी से लेकर आयुर्वेद विश्वविद्यालय की ऑडिट रिपोर्ट में भी गड़बड़ियां सामने आई हैं। नियुक्तियों से लेकर संस्थान के सामान खरीदने में भारी वित्तीय अनियमितताएं देखी गई हैं।

सुप्रीमकोर्ट में याचिका के बाद पेड़ों के कटान पर रोक

देहरादून (संवाददाता)। सहस्रधारा रोड के चौड़ीकरण में पेड़ों के कटान को लेकर सुप्रीमकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। आखिरकार सुप्रीमकोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। बताया कि अभी तक 480 यूकेलिप्टस के पेड़ काटे गए, जबकि 295 ट्रांसप्लांट किया गया।

सहस्रधारा रोड के चौड़ीकरण को लेकर पेड़ों के कटान पर हाईकोर्ट की ओर से रोक लगाने के बाद काटन और ट्रांसप्लांटेशन का काम रोक दिया गया है। उधर, कोर्ट के फैसले के बाद पर्यावरणविदों, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई है।

याचिकाकर्ता एवं पर्यावरणविद् आशीष गर्ग ने बताया कि सहस्रधारा रोड के चौड़ीकरण में पेड़ों के कटान को लेकर सुप्रीमकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। आखिरकार सुप्रीमकोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। बताया कि अभी तक 480 यूकेलिप्टस के पेड़ काटे गए, जबकि 295 ट्रांसप्लांट किया गया।

कहा कि कोर्ट ने फ्लिहाल पीडब्ल्यूडी और वन विकास निगम की ओर से काटे जा रहे पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी है। बताया कि 17 अगस्त को दोबारा सुनवाई होगी।

उन्होंने कहा कि फ्लिहाल कोर्ट के फैसले से राहत मिली है और पेड़ों की जिंदगी को बचाया जा सकेगा। कहा कि जिन पेड़ों को काटा जा रहा, उन्हें काटने की जरूरत ही नहीं है। कहा कि मसूरी और सहस्रधारा के लिए वैकल्पिक मार्ग भी बनाया जा सकता है।

सहस्रधारा में चौड़ीकरण का तमाम पर्यावरणविद और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता लगातार पिछले एक साल से विरोध कर रहे हैं।

आयुर्वेदिक फार्मेसिस्टों के खाली पदों पर हुई नियुक्तियां, 69 अभ्यर्थियों की सूची जारी

देहरादून(संवाददाता)। उत्तराखंड में आयुर्वेद विभाग ने फार्मेसिस्ट पद के लिए आदेश जारी करते हुए 69 रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों की सूची जारी की है। आयुर्वेद विभाग के निदेशक डॉ अरुण कुमार त्रिपाठी ने अभ्यर्थियों की सूची जारी करते हुए तैनाती स्थल पर 15 दिनों के भीतर उपस्थिति दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही ऐसा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी। उत्तराखंड के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में खाली चल रहे फार्मेसिस्ट के पदों को अब भर दिया गया है। हाल ही में चयनित किए गए 69 अभ्यर्थियों की सूची जारी करते हुए आयुर्वेद विभाग ने सभी को तैनाती स्थल दे दिए हैं। इन सभी फार्मेसिस्ट को उन जिलों के चिकित्सालय में भेजा गया है, जहां पर लंबे समय से पद रिक्त चल रहे थे।

हालांकि, आयुर्वेद विभाग द्वारा यह नियुक्तियां अस्थाई तौर पर दी गई हैं। रिक्त पदों के सापेक्ष दी गई तैनाती को विभिन्न जिलों में मौजूद राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय और राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय में किया गया है।

निम में होगी राष्ट्रीय स्पोर्ट क्लाइम्बिंग चैंपियनशिप, एशियन गेम्स और ओलंपिक के लिए यहीं से चयनित होगी टीम

उत्तरकाशी (संवाददाता)। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (हुड्डुरू) के स्पोर्ट क्लाइम्बिंग सेंटर में राष्ट्रीय स्पोर्ट क्लाइम्बिंग चैंपियनशिप होगी। इसके लिए इन दिनों निम में तैयारियां चल रही हैं।

यह चैंपियनशिप 12 अगस्त से 14 अगस्त तक होनी है। जिसके बाद निम से ही एशियन गेम्स और ओलंपिक के लिए क्लाइम्बिंग टीम चयनित होनी है तथा टीम को प्रशिक्षण दिया जाना है।

राष्ट्रीय स्पोर्ट क्लाइम्बिंग चैंपियनशिप के लिए निम (हुड्डुरू) को पहली बार मेजबानी मिली है। इससे पहले निम में जून माह में नार्थ जोन स्पोर्ट क्लाइम्बिंग प्रतियोगिता हुई थी। जिसमें भारतीय पर्वतारोहण संस्थान नई दिल्ली की अध्यक्ष डा. हर्षवंती बिष्ट सहित पर्वतारोहण की कई हस्तियां शामिल हुईं।

निम का स्पोर्ट कलाइम्बिंग सेंटर अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर बना हुआ है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्पोर्ट क्लाइम्बिंग चैंपियनशिप में देश के अलग-अलग जोन की सात टीमें प्रतिभाग करेंगी। इन सात टीमों में 250 प्रतिभागी होंगे। जो लीड क्लाइम्बिंग, बोल्डरिंग क्लाइम्बिंग, स्पीड क्लाइम्बिंग में प्रतिभाग करेंगे।

निम में भारत का पहला इंडोर स्पोर्ट क्लाइम्बिंग सेंटर

राष्ट्रीय स्तर की यह चैंपियनशिप भारतीय पर्वतारोहण संस्थान और निम के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। निम के प्रधानाचार्य और भारतीय पर्वतारोहण संस्थान नार्थ जोन के चेयरमैन कर्नल अमित बिष्ट ने कहा कि निम में भारत का पहला इंडोर स्पोर्ट क्लाइम्बिंग सेंटर है।

इस सेंटर में स्पोर्ट क्लाइम्बिंग की प्रतिभाओं का तराशा जा रहा है। जो भविष्य में ओलंपिक और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर सकेंगे। जून माह में नार्थ जोन की प्रतियोगिता में सात राज्यों के 150 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था।

कर्नल अमित बिष्ट ने बताया कि गत वर्ष टोक्यो ओलंपिक गेम्स के स्पोर्ट क्लाइम्बिंग में स्पेन के अल्बेट्रो गिनेज ने पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। जबकि स्लोवेनिया की जंजा गार्नब्रेट ने महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। जिससे अब स्पोर्ट क्लाइम्बिंग केवल शौकिया सहासिक खेल नहीं है बल्कि स्पोर्ट क्लाइंबिंग में पदक और रोजगार भी जुड़ गया है।

भारतीय पर्वतारोहण संस्थान नार्थ जोन के चेयरमैन कर्नल अमित बिष्ट कहते हैं कि उत्तरकाशी और निम के लिए यह बड़े सौभाग्य और गर्व की बात है कि क्लाइम्बिंग स्पोर्ट की राष्ट्रीय स्पर्धा उत्तरकाशी निम में होने जा रही है। देश के 250 प्रतिभागियों में से उत्तराखंड के आठ खिलाड़ी शामिल होंगे। जो सब जूनियर, जूनियर और सीनियन वर्ग में प्रतिभाग करेंगे।

ये प्रतिभागी देश भर से आने वाली क्लाइम्बिंग स्पोर्ट टीम में साउथ जोन, नार्थ जोन, ईस्ट जोन, नार्थ ईस्ट जोन, आर्मी सर्विसेज टीम और पैरा मिलिट्री टीम में शामिल हैं। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के शुभारंभ के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आमंत्रित किया गया है। साथ ही पर्वतारोहण की कई हस्तियां भी मौजूद रहेंगी।

मंत्री ने ली उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद की बैठक

लाभार्थियों को आवास आवंटित करने के दिए निर्देश

देहरादून (सू.वि.)। आवास एवं शहरी विकास मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद की 12वीं बोर्ड बैठक विधानसभा में ली। इस मौके पर मंत्री डा. अग्रवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही जिन परियोजनाओं में कार्य आरंभ हो चुका है, उनमें लाभार्थियों को आवास आवंटन की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए पात्र लाभार्थियों को आवंटन करने के भी निर्देश दिए।

विधानसभा स्थित मीटिंग हॉल में आयोजित बैठक में आवास एवं शहरी विकास मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने व निरंतर पर्यवेक्षण के लिए निर्देशित किया।

डा. अग्रवाल ने कहा कि परिषद स्तर पर भवन उपविधि के अंतर्गत सभी प्रकार के टाउनशिप योजनाओं के लिए आवास आयुक्त को अधिकृत किया जाए। साथ ही उपविधि के अनुसार टाउनशिप योजनाओं में कार्य करने के निर्देश दिए तथा निजी सहभागिता को प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिए। डा. अग्रवाल ने परिषद की राजस्व वृद्धि करने के भी निर्देश दिए तथा रिक्त संपत्तियों के आवंटन एवं नीलामी के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए भी निर्देशित किया। डा. अग्रवाल ने कहा कि पूर्व में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा आवंटित संपत्तियों में धनराशि जमा करने के लिए तीन माह का समय प्रदान किया जाए।

डा. अग्रवाल ने कहा कि ऐसे आवंटियों, जिनके द्वारा पूर्व में आंशिक भुगतान किया गया है, मगर रोक के कारण उनकी रजिस्ट्री नहीं हो सकी है। उन्हें छह माह का समय बिना किसी दंड ब्याज के बकाया जमा करने के निर्देश दिए। साथ ही यदि कोई एकमुश्त धनराशि तीन माह के भीतर जमा करता है, तो उसको दो प्रतिशत की छूट देने के लिए भी निर्देशित किया।

डा. अग्रवाल ने परिषद के कार्यों को ऑनलाइन करने के लिए आईटी एक्सपर्ट की सेवा आउटसोर्स से लेने के लिए निर्देशित किया। साथ ही परिषद को 50 पदों का ढांचा तैयार करने को भी कहा है।

इस मौके पर अपर मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन, आयुक्त आवास सुरेंद्र नाथ पांडेय, अपर आयुक्त पीसी दुमका, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के संयुक्त आवास आयुक्त राजीव कुमार सहित विभागीय अधिकारी उत्तम सिंह चौहान, एसएम श्रीवास्तव, आनंद सिंह, अमिता जोशी आदि उपस्थित रहे।

आवास एवं विकास परिषद की बैठक में शिरकत करते काबीना मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ।

उत्तराखंड में कोरोना के 294 नए केस

देहरादून (संवाददाता)। उत्तराखंड में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 294 नए मरीज मिले हैं। जबकि 212 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। इसके साथ एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,905 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। प्रदेश में सैंपल पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 12.39 है.उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, एक जनवरी 2022 से लेकर अभी तक प्रदेश में 99,717 मामले सामने आ चुके हैं। जिसमें से 93,977 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 94.24त्न है। वहीं, इस साल अब तक 299 मरीजों की मौत हुई है।

पिछले 24 घंटे में देहरादून में 144 कोरोना केस मिले हैं। वहीं, हरिद्वार में 16, नैनीताल में 56 कोरोना मरीज मिले हैं। जबकि, अल्मोड़ा में 15, बागेश्वर में 1, चमोली में 2, चंपावत में 2, पौड़ी में 19 केस मिले हैं। इसके अलावा पिथौरागढ़ में 3, रुद्रप्रयाग में 19, टिहरी में 6 और उधम सिंह नगर में 11 मरीज मिले हैं।

कोविड वैक्सीनेशनः प्रदेश में शनिवार को 26,185 लोगों का कोविड वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक कुल 86,32,806 लोग फुल वैक्सीनेट हो चुके हैं। वहीं, 15 से 17 साल तक के 4,49,161 बच्चों को दोनों डोज और 12 से 14 साल के 2,80,251 बच्चों को दोनों डोज लग चुकी है।

दून में पहली बार मिला दुर्लभ वाइट लिप्ड पिट वाइपर

देहरादून (संवाददाता)। सहस्त्रधारा रोड पर वन विभाग की क्विक रिएक्शन टीम(क्यूआरटी) ने दुर्लभ वाइट लिप्ड पिट वाइपर सांप पकड़ा। ये बेहद जहरीला सांप देहरादून में पहली बार रेस्क्यू किया गया है।

रेस्क्यू टीम लीडर जितेंद्र बिष्ट में बताया कि सहस्त्रधारा निवासी ऋषभ काला ने घर मे सांप होने की सूचना दी। जिस पर रेस्क्यू टीम ने जाकर इस सांप को पकड़ा। ये गहरे हरे रंग के कारण आसानी से घास व पेड़ो में छिप जाता है।

इस कारण इसे खोजना काफी मुश्किल होता है। इसे पकड़ने वाली टीम में सुदर्शन पंवार भी मौजूद थे।

आज भी लोगों के सूखे हलक तर कर रहा 194 साल पुराना ये कुआं

◆ इसलिए कहते हैं इसे विशिंग वेल

मसूरी (संवाददाता)। 'मेरी उम्र 194 साल है, पर ख्वाहिश अभी मरी नहीं है। अब भी मैं सूखे हलक को तर करने का काम करता हूं। कोई भी प्यासा मेरे पास आता है, मैं उसको बिन पानी तड़पने नहीं देता है। हां! इस वक्त मैं तो ठीक हूं, लेकिन मेरी बाह्य दशा को मुलाजिमों ने जीर्णशीर्ण स्थिति में पहुंचा दिया है। फिर भी लोगों की प्यास बुझाने का जज्बा कम नहीं हुआ है और मैं अपने काम को बिना लागलपेट के निरंतर किए जा रहा हूं।'

उपरोक्त जज्बा और दर्द मसूरी के हाथीपांव के उस ऐतिहासिक 194 साल पुराने कुएं के हैं, जो बोल तो नहीं सकता, लेकिन दशा देखकर उसकी पीड़ा को बखूबी समझा जा सकता है।

निर्जीव होने के बावजूद जीवितों की प्यास बुझा रहा है, लेकिन अफसरों और कर्मियों की बेरुखी से जीर्णशीर्ण हालत में पहुंच गया है।

अमूमन पहाड़ों में पानी के कुएं इतनी ऊंचाई पर नहीं होते है, लेकिन मसूरी में ऐतिहासिक कुआं है, जो पानी देने के बावजूद अपनी जीर्णशीर्ण दशा पर आंसू भी बहा रहा है। अब इसमें धीरे-धीरे पहले के मुकाबले पानी भी कम हो रहा है। प्रदेश के सभी हिल स्टेशनों में संभवतयाः यह पहला कुंआ है, जो इतनी ऊंचाई पर अंग्रेजों ने बनाया था।

कुएं में भले ही पहले के मुकाबले पानी कम हो गया हो, लेकिन आज भी आसपास के लोग इसके पानी पर निर्भर हैं। हाथीपांव, जॉर्ज एवरेस्ट, क्लाउड एंड, दूधली समेत आसपास आने वाले पर्यटक कुएं को देखने जरूर आते हैं।

इसे लेकर शहर के पुराने लोगों में कई मान्यताएं भी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि कुएं में पीछे मुड़कर कोई सिक्का या अंगूठी डालेगा, तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। आज भी कई लोग क्षेत्र में जब घूमने आते हैं, तो कुएं में सिक्का जरूर डालते हैं। इससे कुएं का नाम विशिंग वेल भी पड़ गया है।

1828-29 में तत्कालीन अंग्रेज जनरल विश ने मसूरी के हाथीपांव में पानी न होने पर सात हजार फीट की ऊंचाई पर कुएं का निर्माण कराया था। शहर में पानी की कमी से भले ही लोग परेशान रहते हों, लेकिन कुएं के आसपास के लोगों को इससे लगातार पानी मिल रहा है।

हाथीपांव क्षेत्र में लगातार आबादी बढ़ने और वन क्षेत्र कम होने का असर कुएं के पानी पर भी देखने को मिल रहा है।

पहले के मुकाबले पानी कम हो गया। बुजुर्ग रूप सिंह कठैत बताते हैं कि आज भी आसपास के लोग इसी कुएं से प्यास बुझा रहे हैं।

दुख जताया कि ऐतिहासिक महत्व के कुएं का उचित रखरखाव न होने से इसकी हालत दयनीय होती जा रही है। क्षेत्र में पानी की कमी दूर करने के लिए अंग्रेज जनरल विश ने कुएं का निर्माण कराया था। सर जार्ज एवरेस्ट ने भी कुएं के पानी का इस्तेमाल किया था।

आज भी यह लोगों की प्यास बुझा रहा है, लेकिन रखरखाव न होने से इसकी हालत जहां जीर्णशीर्ण होने लगी है तो वहीं पानी भी कम होता जा रहा।

मसूरी में हाथीपांव में ऐतिहासिक कुआं

शांतिपुरी में रात को तेंदुएं देखे जाने से ग्रामीणों में दहशत

रुद्रपुर (संवाददाता)। शांतिपुरी में देर रात को घरों के नजदीक तेंदुए की जोड़ी को देखे जाने के बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई। लोग अपने-अपने घरों से निकल कर मोहल्ले में इकट्ठा हो गए और ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों के साथ मिलकर तेंदुए को भगाने के लिए हांका लगाया।

वहीं वन विभाग के सुरक्षाकर्मियों ने करीब 5 राउंड फायरिंग भी की।गुरुवार देर रात को शांतिपुरी नंबर दो निवासी सुनील मिश्रा सत्यपुर गांव से अपने घर आनंदपुर की ओर आ रहे थे तभी उनको गांव के मुहाने पर मनोहर जोशी के खेत के पास तेंदुओं की जोड़ी को रास्ता पार करते हुए देख लिया। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय ग्रामीणों को दी। जिस पर ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर टॉर्च इत्यादि सर्च लाइटों से देखा तो खेतों में तेंदुए की जोड़ी दिखाई दी। सूचना वन क्षेत्राधिकारी रेंजर अनिल जोशी को दी और तत्काल मौके पर डिप्टी रेंजर मनोज जोशी के नेतृत्व में टीम पहुंच गई। जिसके बाद वन कर्मियों और ग्रामीणों ने साथ मिलकर हांका लगाया और करीब पांच राउंड फायरिंग कर तेंदुए को भगाने का प्रयास किया।

इसके बाद तेंदुए गन्ने के खेतों में ओझल हो गए। बावजूद इसके सुरक्षा दृष्टि को ध्यान में रखते हुए वन विभाग की टीम रात भर हूटर बजाकर गस्त करती रही। वहीं ग्रामीण भी अपने घरों के बाहर लाइटें खुली रख जाग करते रहे।

स्वामी मुद्रक, प्रकाशक मोहन राजा द्वारा आर. के. प्रिन्टर्स 43/1, धर्मपुर माता मन्दिर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड से मुद्रित कराकर 95 बी शुभम विहार, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित किया

सम्पादक

मोहन राजा

फोन नं0- 01334-212184

Mob- 9997426600

कानूनी सलाहकार

एडवोकेट : के. पी. सिंह (देहरादून)

सभी विवादों का न्याय क्षेत्र देहरादून होगा

e-mail

kkalamkasauda@yahoo.in